

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,
अपर सचिव न्याय एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन, देहरादून ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल ।

न्याय अनुभाग : 1

देहरादून : दिनांक : 26 सितम्बर, 2006

विषय: अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष शासन द्वारा आवद्ध किये गये शासकीय अधिवक्ताओं की फीस निर्धारण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 43-एक(1)/न्याय अनुभाग/2003 दिनांक 26 फरवरी, 2003 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल उत्तरांचल के जिलों में स्थित दीवानी/राजस्व/फौजदारी के न्यायालयों में शासन का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु आवद्ध अधिवक्ताओं को दिनांक 01 सितम्बर, 2005 से फीस में वृद्धि करते हुए निम्न विवरणानुसार फीस का भुगतान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

**जिला न्यायालय
दीवानी/राजस्व/फौजदारी**

रिटनर फीस

दिनांक 1.9.2005 से प्रभावी दरें

1- जिला शासकीय अधिवक्ता	रु0 1875/- प्रतिमाह
2- अपर जिला शासकीय अधिवक्ता	रु0 1500/- प्रतिमाह
3- सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता	रु0 1315/- प्रतिमाह
4- उप जिला शासकीय अधिवक्ता	रु0 1125/- प्रतिमाह

ड्राफ्टिंग

1- वाद/अपील/मेमो/प्रार्थना-पत्र पुनरीक्षण, प्रार्थना-पत्र (रिवीजन)	रु0 300/- प्रतिकेस
2- लिखित विवरण/पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र (रिब्यू)	रु0 150/- प्रतिकेस

उपर्युक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित प्रार्थना-पत्र का आशय केवल सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-9, नियम-13 के प्रार्थना-पत्र से होगा । अन्य किसी प्रार्थना-पत्र के लिए कोई फीस अनुमन्य नहीं होगी ।

जिला न्यायालयों में कार्यरत प्रत्येक जिला शासकीय अधिवक्ता दीवानी, फौजदारी, राजस्व को शासनादेश संख्या 43-एक(1)/न्याय अनुभाग/2003 दिनांक 26 फरवरी, 2003 के अनुसार आशुलिपिक

कार्य हेतु रुपया 2000/- प्रतिमाह तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्य हेतु रु0 1000/- प्रतिमाह की दर से भत्ता देय होगा, जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आशुलिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। भत्तों का भुगतान यह प्रमाणित करने पर होगा कि उन्होंने उक्त धनराशि इस कार्य हेतु व्यय की है।

बहस

- 1- जिला शासकीय अधिवक्ता को वादों तथा प्रकीर्ण वादों में बहस हेतु। रु0 465/- प्रतिदिन
- 2- अपर/सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता/विशेष अधिवक्ता/एमीकसक्यूरी/नामिका वकील (दीवानी/फौजदारी/राजस्व) को वादों तथा प्रकीर्ण वादों में बहस हेतु। रु0 425/- प्रतिदिन
- 3- उप जिला शासकीय अधिवक्ता को वादों तथा प्रकीर्ण वादों में बहस हेतु। रु0 375/- प्रतिदिन

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय व्ययक में अनुदान संख्या 04 के लेखा शीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)-04-विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता-00-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 543/वित्त अनुभाग-5/06 दिनांक 11 सितम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव।

संख्या: 135-XXXVI(I)/2006तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून।
- 2- रामस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तरांचल।
- 3- विशेष कार्याधिकारी, मुख्य मंत्री को मा० मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
- 4- रामस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
- 5- एन.आई.सी./गार्ड बुक।

आज्ञा से,
22/12
(एम0 एम0 सेमवाल)
अनु सचिव।